आकाशवाणी केन्द्र शिमला
22.03.2026 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में लगातार सबसे लम्बे समय तक सरकार के मुखिया बने रहने का कीर्तिमान किया स्थापित।
- मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा– अगले वित्त वर्ष का बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित– वित्तीय हालत सुधारने के लिए उठाए जाएंगे ठोस कदम।
- प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बजट में कटौती को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की, कहा– विकास कार्यों पर पड़ेगा विपरीत असर।
- उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सभी लोगों को शुद्ध पेयजल व हर खेत को सिंचाई सुविधा देने को बताया राज्य सरकार की प्राथमिकता।
- एस.डी.आर.एफ. ने लगातार दूसरी बार जीती आपदा में राहत व बचाव कार्यों पर आधारित राष्ट्रीय प्रतियोगिता।

प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश में किसी निर्वाचित सरकार का सबसे अधिक समय तक नेतृत्व करने वाले पहले शासनाध्यक्ष बन गए हैं। नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर संयुक्त रूप से आज 8 हजार 9 सौ 31 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है। उनसे पहले पवन कुमार चामलिंग 8 हजार 9 सौ 30 दिन तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे। नरेन्द्र मोदी 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 2014 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। वे लगातार तीन बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले गैर–कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री को देश व प्रदेश के नेताओं ने बधाई दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि विकास को राजनीति का आधार बनाया जा सकता है और उन्होंने प्रधान सेवक के रूप में देश की राजनीति को एक नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और अगले वित्त वर्ष के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकास की धुरी के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि व्यवस्था परिवर्तन पर केन्द्रित ये बजट गांवों को समृद्धि का प्रमुख केन्द्र बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने बताया कि अगले 6 महीने में प्रदेश की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे और बजट में इसका प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के वेतन में कटौती का प्रावधान इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।

बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अगले वित्त वर्ष के बजट में कटौती करने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के बजट में हर साल 3 से 4 हज़ार करोड़ रूपए की बढ़ोतरी होती रही है लेकिन हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बजट में कटौती की गई हो।

बिंदल ने कहा कि इस कटौती का प्रदेश के विकास कार्यों पर सीधा असर पड़ेगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 3 सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी लेकिन बजट भाषण में चुनिंदा लोगों को ही मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश के सभी लोगों को शुद्ध पेयजल व हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए जलशक्ति विभाग लगातार काम कर रहा है। विश्व जल दिवस पर आज सोलन ज़िले के बद्दी में आयोजित राज्यस्तरीय जल महोत्सव समारोह में उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारी व कर्मचारी 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उपमुख्यमंत्री ने दून व नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए दो–दो करोड़ रूपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों क्षेत्रों में जलशक्ति विभाग में 50–50 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि नालागढ़–बद्दी राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन कार्य की निविदा का मामला केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से उठाया जाएगा।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने आज नागपुर में भारतीय युवा संसद के राष्ट्रीय सत्र को संबोधित किया। इसमें देशभर से लगभग 6 सौ युवा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि उसकी आत्मा, स्मृति व जीवंत पहचान होती है। उन्होंने युवाओं से अपनी मातृभाषा पर गर्व करने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में आज के युवाओं की ऊर्जा, नवाचार व प्रतिबद्धता सहायक सिद्ध होगी।

केवल सिंह पठानिया

उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि प्रदेश का अगले वित्त वर्ष का बजट जनकल्याण व समग्र विकास को समर्पित है। कांगड़ा ज़िले के शाहपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बजट में राज्य सरकार ने गेहूं, मक्का, जौ और हल्दी के समर्थन मूल्य में बढ़ोत्तरी की है जबकि अदरक के लिए भी पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। पठानिया ने कहा कि बजट में विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोज़गार सृजन पर ध्यान दिया गया है।

भाजपा

इस बीच, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के बजट प्रस्ताव को गलत बताया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में अगले 6 महीने के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की बात कही गई है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि इस समय प्रदेश वित्तीय आपातकाल से गुज़र रहा है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना बढ़ती जा रही है।

एसडीआरएफ

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, एस.डी.आर.एफ. ने गाज़ियाबाद में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगातार दूसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। आपदा के कारण ध्वस्त ईमारतों के मलबे में फंसे लोगों की खोज व बचाव पर आधारित इस प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों की 30 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में एस.डी.आर.एफ. की टीम के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि एस.डी.आर.एफ. की ये उपलब्धि प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और आपदा के दौरान एस.डी.आर.एफ. ने पिछले कुछ वर्षों में बेहतरीन कार्य किया है।